राजस्थान बजट 2015–16

उद्योग व्यापार पर जोर, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्र पीछे

राजस्थान सरकार के वर्ष 2015–16 के बजट में, जैसा कि अपेक्षित था, काफी जोर उद्योग व्यापार के लिये सुविधाएं देने, करों की प्रकिया को आसान करने, आर्थिक आधारभूत ढांचे को बढ़ाने, तथा कौशल विकास पर रहा है। हालांकि बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने आर्थिक आधारभूत ढांचा के विकास के साथ–साथ मानव संसाधन सामाजिक ढांचागत विकास, जल संरक्षण को भी आवश्यक बताया।

परन्तु बजट भाषण में अधिकांश समय ई– गर्वनेंस, कर संग्रहण प्रकिया में सुधार, राज्य में निवेश बढ़ाने के उपायों, राज्य में सड़कों के विस्तार को दिया गया। पिछले बजट में जहां 20,000 किमी. सड़क निर्माण निजी – सार्वजनिक सहभागिता से करवाने की घोषणा की गई थी, वहीं इस बार आगामी वर्ष में 10,000 किमी. और सड़क बनाने और नवीनीकरण करने की घोषणा की गई है। वर्ष 2015–16 में पांच राज्य मार्गों का निर्माण कार्य आरम्भ करने की घोषणा भी की गई। अच्छी बात यह रही कि 4,000 किमी. ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण की घोषणा भी की गई है, साथ ही 50 करोड़ रूपये खान क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये रखे गये हैं।

राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS 2014) पर निर्भरता जतायी गई है, जिसमें पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों तथा मुख्य क्षेत्रों (Thrust Secters) की पहचान कर उनके प्रोत्साहन के प्रावधान किये गये हैं। इसके साथ ही करों की प्रक्रिया सरल करने को लेकर ई–गर्वेनेंस से सम्बन्धित कई घोषणाए की गई हैं।

जहां तक सामाजिक क्षेत्र का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में जहां कुछ महन्तवपुर्ण घोषणाएं की गई हैं, जैसे सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने तथा जिला शिक्षा समिति का गठन जो जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देगा तथा जिला शिक्षा रिर्पोट भी जारी करेगा। इसके अलावा पिछले वर्ष घोषित 63 मॉडल स्कुलों को अब तीन वर्ष में पूरा किया जायेगा। साथ ही आगामी तीन वर्षों में 73 वर्तमान मॉडल स्कुलों के भवनों का सुद्वढ़ किया जायेगा।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में राज्य उच्च शिक्षा मास्टर प्लान बनाकर 8 वर्षों में लागू किया जायेगा तथा राज्य में एक विज्ञान एवं मानवीकी शोध संस्थान की गठन किया जायेगा।

पेयजल क्षेत्र में पिछले वर्ष कुल 52 अधुरी परियोजनाओं में से 12 को पूरी करने की घोषणा की गई थी। इस वर्ष सरकार ने 12 और अधुरी योजनाओं को पूरा करने की घोषणा की है। पेयजल के लिये कुछ और योजनाएं भी घोषित की गई हैं। लेकिन कृषि, ग्रामिण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों और महिलाओं, बच्चों , दलितों, आदिवासीयों तथा अल्पसंख्यकों के बजट में विशेष वृद्वि नहीं हुई है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का कुल आंवटन 5200 करोड़ रूपये हुआ है जो वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान के बराबर ही है। यह अत्यंत महत्वपुर्ण है क्योंकि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र जिस पर राज्य की आधी से अधिक आबादी निर्भर है, की वृद्विदर में गिरावट आई है तथा इस वर्ष भी यह मात्र 2.5 प्रतिशत रहा है।

राज्य की वित्तीय स्थिति : वर्तमान वर्ष में घाटे में बढ़ोतरी

जहां तक राज्य की वित्तीय स्थिति का सवाल है तो वर्ष 2014–15 में संशोधित अनुमान के अनुसार 4 हजार करोड़ का राजस्व घाटा होना अनुमानित है, जो मुख्यतः इस वर्ष केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा केन्द्रीय अनुदान में बजट अनुमान से कम आय रहने तथा राज्य के स्वंय के करों में भी कमी आने के कारण हुआ है।

इस कारण सरकार को वर्तमान वर्ष में बजट अनुमानों से 10 हजार करोड़ रूपये अधिक का कर्ज लेना पड़ा है। साथ ही वर्ष 2014–15 में राज्य में आयोजना तथा पूंजीगत खर्च में बजट अनुमानों की अपेक्षा कमी आई है। वहीं 2014–15 में राजस्व घाटे के साथ–साथ राजकोषिय घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद के 3.52 प्रतिशत से बढ़कर संशोधित अनुमान के अनुमान के अनुसार 4 प्रतिशत हो गया है।

केन्द्र सरकार से प्राप्त संसाधनों मे परिवर्तन

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्राप्त होने वाले संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन का असर भी इस बजट पर दिखा है। वर्ष 2015–16 में एक तरफ जहां केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में 9000 करोड़ रुपये की बढोतरी हुई है वहीं केन्द्र से प्राप्त अनुदानों में 3000 करोड़ रुपये की कमी आई है। बजट अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2015–16 में आयोजना व्यय पिछले वर्ष के बजट अनुमान के बराबर ही रहेगा जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा इसमें करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार पूंजीगत खर्च में इस वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में मात्र 1500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गयी है। जबकि राजस्व व्यय तथा गैर आयोजना व्यय में जरुर बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार इस वर्ष बजट में 500 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य तथा राजकोषिय घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद का

मात्र 2.99 प्रतिशत होना अनुमानित है, परंतु वास्तविक स्थिति सरकार के कर संग्रहण के उपायों के लागू होने तथा सरकारी खर्चों के बजट के अनुरुप बने रहने पर निर्भर करेगी।

अंत मे.....

कुल मिलाकर इस बजट में आगामी वर्ष में जहां घाटे पर नियंत्रण रखने के साथ–साथ राज्य में उद्योग व्यपार के लिये अनुकुल माहौल बनाने पर जोर है वहीं कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान कम रहा है। कृषि क्षेत्र, जिस पर राज्य की आधी से अधिक से आबादी निर्भर है, की वृद्धि की दर इस वर्ष मात्र 2.5 प्रतिशत रही है। ऐसे में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा से राज्य में तीव्र आर्थिक विकास की संभावना कमजोर भी पड़ सकती है।